



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1941 (श0)
(सं0 पटना 500) पटना, शुक्रवार, 29 मार्च 2019

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 2019

एस0ओ0, 80 दिनांक 29 मार्च 2019—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 49) की धारा-3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पूर्व निर्गत सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण एवं उनके अधीन की गई सभी कार्रवाईयों की व्यावृत्ति करते हुए, बिहार सरकार उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से राज्य सरकार के किसी अनुसंधान एजेंसी के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधानित, उक्त अधिनियम की धारा-3 अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 (1947 का 2) के अधीन उसके तत्स्थानी प्रावधानों के अधीन प्रगणित अपराधों के विचारण हेतु कॉलम-2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्थान पर विशेष न्यायाधीश का एक न्यायालय गठित करती है।

किसी ऐसे मामले का विचारण करते समय, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-3 में प्रगणित अपराध के साथ किसी ऐसे अपराध का, जिससे अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 4) के अधीन उसी विचारण पर आरोपित हो, विचारण भी कर सकेंगे।

पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में पदस्थापित संबंधित विशेष न्यायाधीश इसके अधीन कॉलम-3 में यथा विनिर्दिष्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे:-

क्रमांक	विशेष न्यायाधीश के न्यायालय का स्थान	क्षेत्रीय अधिकारिता
1	2	3
1	पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर (भभुआ), गया, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद

क्रमांक	विशेष न्यायाधीश के न्यायालय का स्थान	क्षेत्रीय अधिकारिता
1	2	3
2	मुजफ्फरपुर	सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर
3	भागलपुर	भागलपुर, बाँका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णियाँ

(सं० सं०-ए०/एक्ट०-14/2006/2548/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

27 मार्च 2019

एस०ओ० 81, एस०ओ० 80 दिनांक 29 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/एक्ट०-14/2006/2548/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

The 27th March 2019

S. O. 80 dated 29th March 2019— In exercise of the powers conferred by section-3(1) of The Prevention of Corruption Act, 1988 (Act 49 of 1988) and in supersession of all earlier notifications issued in this regard, while saving all actions taken thereunder, the Government of Bihar in consultation with the High Court of Judicature at Patna, constitutes a court of Special Judge at each of the places specified in column 2 to try the offences enumerated under Section 3 of the said Act or its corresponding provisions under the Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947) investigated by a police officer of any investigating agency of the State Government.

When trying any such case, the Special Judge may also try any offence other than an offence enumerated in Section-3 of the Prevention of Corruption Act, 1988, with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be charged at the same trial.

The respective Special Judges posted at Patna, Muzaffarpur and Bhagalpur shall exercise their jurisdiction, as specified in column 3 hereunder:-

Sl. No.	Place of Courts of Special Judges	Territorial Jurisdiction
1	2	3
1	Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Buxar, Rohtas, Kaimur at Bhabhua, Gaya, Aurangabad, Nawada and Jehanabad
2	Muzaffarpur	Saran, Siwan, Gopalganj, Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali, Sheohar, East Champaran, West Champaran, Darbhanga, Madhubani and Samastipur
3	Bhagalpur	Bhagalpur, Banka, Munger, Sheikhpura, Jamui, Khagaria,

Sl. No.	Place of Courts of Special Judges	Territorial Jurisdiction
1	2	3
		Lakhisarai, Begusarai, Supaul, Saharsa, Madhepura, Kishanganj, Araria, Katihar and Purnea.

(File No.-A/Act -14/2006/2548/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

AKHILESH KUMAR JAIN,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 500-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>